@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

‘प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित है यह आम बजट’

वर्ष-15, अंक-04 16-29 फरवरी, 2020 (पाक्षिक) ₹20

जन-जन का बजट

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा साथ में–भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी. एल. संतोष, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह व अन्य

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट करते श्री जगत प्रकाश नड्डा

ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल व बोडो प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में संपन्न हुई सैन्य प्रदर्शनी, 2020 के दौरान एक पुस्तिका का विमोचन करते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार चलती–फिरती मधुवाटिका का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011- 23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **ग्रामीण विकास में तेजी, नौजवानों के लिए रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला बजट**

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2020-21 प्रस्तुत किया। बजट में ग्रामीण विकास में तेजी, नौजवानों के लिए रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर...

वैचारिकी

आत्मिक सुख की आवश्यकता 22

श्रद्धांजलि

नहीं रहे पी. परमेश्वरन 24

लेख

गंगा शुद्धि का भगीरथ प्रयास 30

बजट 2020 किसान हितैषी एवं विकासोन्मुख है 31

अन्य

केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य बातें 08

प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित है... 13

किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ... 14

बोडो समझौता असम में नया सवेरा लाएगा: प्रधानमंत्री 26

संसद ने नयी सरकार के गठन के बाद कई ऐतिहासिक कानून पारित कर रिकॉर्ड बनाया: रामनाथ कोविंद 27

कृषि बजट में पांच गुना की बढ़ोतरी: नरेन्द्र मोदी 28

क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए श्रीलंका सरकार का संकल्प स्वागतयोग्य है... 32

गगनयान मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि 33

11 **समृद्ध नए दशक की नींव रखी गई...**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट 2020 को समृद्ध नए दशक की नींव रखनेवाला, भविष्योन्मुखी और कार्रवाई उन्मुख...

17 **5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए धन सृजन महत्वपूर्ण**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर 'सबका साथ सबका विकास' विजन के साथ किए गए संबोधन में इस बात को प्रमुखता...

18 **संपन्न हुआ ऐतिहासिक बोडो समझौता**

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 50 वर्षों से चले आ रहे बोडो मुद्दे के समाधान के लिये 27 जनवरी को समझौता किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री कहा कि जिस...

20 **श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

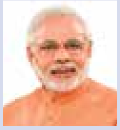

हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये हमारी नीतियों में भी नजर आता है।

राजनाथ सिंह

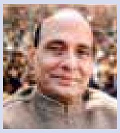

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे रक्षा निर्यात जो 2017-2018 में 66 करोड़ डॉलर के थे अब बढ़कर 2018-2019 में 147 करोड़ डॉलर हो गए हैं। हमारी स्वदेशी और सहयोगी रक्षा उत्पादन क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

अमित शाह

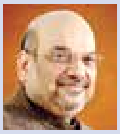

स्वस्थ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए मोदीजी ने आयुष्मान भारत को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए टियर 2 व टियर-3 शहर विशेषकर 112 आकांक्षी जिले जहां आयुष्मान भारत के अंतर्गत कोई अस्पताल नहीं है,वहां पीपीपी मॉडल द्वारा नए अस्पतालों को जोड़ने का सराहनीय कदम उठाया है।

facebook

अपनी रचनाओं से सामाजिक बुराइयों तथा कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एवं समाज को एकता का उपदेश देने वाले महान संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।

— जगत प्रकाश नड्डा

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमोशन में आरक्षण मामले पर फैसले में न कभी भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया और न शपथ पत्र मांगा गया। मामला 5 सितंबर 2012 को उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार द्वारा लिए निर्णय पर आधारित है। भारत सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर समुचित कदम उठाएगी।

— थावरचंद गहलोत

नॉर्थ ईस्ट के 8 चरमपंथी समूहों के 644 विद्रोहियों ने असम के मुख्यमंत्री सर्बदानंद सोनवाल जी की मौजूदगी में अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया.. कुछ दिन पहले यह ब्रू शरणार्थी समस्या हल हुआ.. नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह जी उग्रवादमुक्त उत्तर पूर्व बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

— बी. एल. संतोष

कमल संदेश परिवार की ओर से सुधी पाठकों को

महाशिवरात्रि (21 फरवरी)

की हार्दिक शुभकामनाएं!

बजट 2020—भारत की प्रगति में एक नया मील का पत्थर

बजट 2020 से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प और भी अधिक मजबूत हुआ है। इसने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर बल देते हुए भविष्य की एक उत्साहवर्द्धक रूपरेखा देश के सामने रखी है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था का एक व्यापक चित्र इस बजट से प्रस्तुत हुआ है। जिसमें जन–जन की जरूरतें और आकांक्षाएं परिलक्षित हो रही हैं। यही कारण है कि समाज के हर वर्ग में बजट का स्वागत हुआ है। इसने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान रखते हुए एक सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजटों से निरंतरता स्थापित करता हुआ यह बजट अभिनव योजनाओं से भी परिपूर्ण है। यह बजट इस बात का परिचायक है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, भारत अब एक आत्मविश्वास से ओत–प्रोत राष्ट्र है जो मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाता रहेगा।

'महत्वाकांक्षी भारत', 'सभी के लिए आर्थिक विकास' और 'जिम्मेदार समाज' जैसे तीन सूत्र जिनमें इस बजट को पिरोया गया है, इसे और भी अधिक सर्व-स्पर्शी एवं सर्वसमावेशी बनाता है। 'महत्वाकांक्षी भारत' के अंतर्गत कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर 16-सूत्री कार्यक्रम तथा 2.83 लाख करोड़ के बजटीय आवंटन के माध्यम से विशेष ध्यान दिया गया है जो कि मोदी सरकार के पिछले बजटों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के संकल्प पर आधारित है। साथ ही बजट स्वास्थ्य, जल एवं सिंचाई के विषय जो देश के स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण हैं उन पर विशेष बल दिया है। शिक्षा एवं कौशल पर विशेष बल दिये बिना जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती इसलिए बजट में इस क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया गया है। इससे नए अवसर मिलेंगे और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों का विकास हो पायेगा।

> 'महत्वाकांक्षी भारत', 'सभी के लिए आर्थिक विकास' और 'जिम्मेदार समाज' जैसे तीन सूत्र जिनमें इस बजट को पिरोया गया है, इसे और भी अधिक सर्व–स्पर्शी एवं सर्वसमावेशी बनाता है।

'सभी के लिए आर्थिक विकास' के सूत्र को क्रियान्वित करते हुए बजट में उद्योग एवं व्यापार के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 27,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार आने वाले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए आधारभूत संरचना के विकास के लिए खर्च करने वाली है, जिससे इस क्षेत्र का विकास 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के अनुरूप होगा। आधारभूत पाइपलाइंस, आर्थिक गलियारा, राजपथ, एक्सप्रेस–वे, तटीय तथा बंदरगाह सड़कें, रेलवे का विद्युतीकरण, 100 हवाई अड्डों के निर्माण पर बल से देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य संवारा जा रहा है। 'अंत्योदय' की अवधारणा के आधार पर एक 'जिम्मेदार समाज' के निर्माण को ध्यान में रखते हुए महिला, बच्चे एवं सामाजिक कल्याण पर भी विशेष बल दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 85,000 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजातियों के लिए 53,700 करोड़ रुपयों का प्रावधान इस बजट में है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जनों के लिए भी 9,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने 2014–19 के बीच 7.4 प्रतिशत की दर से विकास किया जबकि मुद्रास्फीति केवल 4.5 प्रतिशत रही। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार को उन अनेक अभिनव पहलों का श्रेय जाता है जिससे देश कांग्रेसनीत यूपीए शासनकाल के भयंकर भ्रष्टाचार, जनता के धन की लूट, 'पॉलिसी पैरेलिसिस' एवं कुशासन से बाहर निकला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता तथा कड़े निर्णय लेने की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही आज यह संभव हो पाया है कि भारत की उपलब्धियों को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' एवं 'इज ऑफ लिविंग' के पैमानों पर प्राप्त उपलब्धियां आज दूसरे देशों के लिए शानदार उदाहरण बन चुके हैं। बजट 2020 हर चुनौती एवं विपरीत परिस्थितियों के सामने उसी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति से आगे बढ़ने का परिचायक है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को जन–जन की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को इस बजट से पूरा करने के लिए बहुत–बहुत बधाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की गौरवशाली यात्रा में यह बजट एक नया मील का पत्थर साबित होगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

ग्रामीण विकास में तेजी, नौजवानों के लिए रोजगार

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2020-21 प्रस्तुत किया। बजट में ग्रामीण विकास में तेजी, नौजवानों के लिए रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर जोर दिया गया। साथ ही, आयकर में कमी लाकर विशेष कर मध्यम वर्ग को राहत दी गई। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, बजट में आम जन के स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया गया है। खासकर नव उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया गया है।

महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज का निर्माण

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में एक फरवरी को प्रस्तुत किये गए केंद्रीय बजट 2020-21 का प्रमुख उद्देश्य महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज का निर्माण करना है। इसलिए बजट में दूर-दराज तक पहुंचने वाले अनेक सुधारों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

‘किसान रेल’ और ‘कृषि उड़ान’ की शुरुआत

किसानों के अनुकूल पहल करके वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य रखा गया है और खराब

> मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बजट में जिन नए रीफॉर्म्स का ऐलान किया गया है, वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे।
>
> **नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

र और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला बजट

होने वाली वस्तुओं के लिए बिना किसी बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय ने क्रमशः 'किसान रेल' और 'कृषि उड़ान' की शुरुआत की है। 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पम्पों को हासिल करने के लिए पीएम कुसुम का विस्तार किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र के लिये 16 सूत्रीय कार्ययोजना

वित्त मंत्री ने ढांचागत परियोजनाओं, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार 16 सूत्रीय कार्ययोजना का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि सेवाओं में व्यापक निवेश की जरूरत है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य' योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है और 2024 तक 2000 औषधियों और 300 सर्जिकलों की सभी जिलों को पेशकश करते हुए जन औषधि केन्द्र योजना लागू की गई है।

उड़ान योजना को सहयोग प्रदान करने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जाएगी और पीपीपी मोड के जरिए 150 यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। मार्च, 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के जरिए एप्रेंटिसशिप की शुरुआत की जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने के साथ ही सस्ते मकानों पर कर लाभ बढ़ाने और कंपनियों पर लाभांश वितरण कर समाप्त करने की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2020-21 का बजट पेश करते हुये रसोई और भोजन की मेज पर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों, बिजली के सामान से लेकर चप्पल जूते, फर्नीचर, स्टेशनरी और खिलौनों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। इससे 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलने और घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से सुरक्षा मिलेगी।

आयकर का सरलीकरण

श्रीमती सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुये व्यक्तिगत आयकर दाताओं को घटी दरों के साथ वैकल्पिक आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया। 5 लाख रुपये तक की आयकर मुक्त रहेगी। सात स्लैब वाली नई प्रस्तावित कर व्यवस्था में मौजूदा पांच, 20 और 30 प्रतिशत की कर दर के अलावा 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के नये स्लैब शामिल किये गये हैं। आयकर की नई व्यवस्था वैकल्पिक रखी गई है और जो करदाता अलग अलग रियायतें और कटौतियां नहीं लेना चाहेंगे, वह इस नई व्यवस्था को अपना सकते हैं।

बजट के अनुसार प्रस्तावित वैकल्पिक नए आयकर ढांचे को चुनने वाले करदाताओं को आयकर कानून की धारा 80सी और 80डी, यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, पेशेवर कर और खुद के मकान अथवा खाली पड़ी संपत्ति के आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाले कर लाभ और कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

वित्त मंत्री ने बाद में संवाददाताओं से कहा, 'हमारा लक्ष्य आने वाले समय में आयकर पर रियायतों और कटौतियों की व्यवस्था को समाप्त करना है।'

'विवाद से विश्वास' योजना

वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में व्यापक सुधार उपायों को आगे बढ़ाते हुये पुराने विवादित कर मामलों का निपटान करने के लिये 'विवाद से विश्वास' योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक करदाता यदि भुगतान करता है तो केवल विवादित राशि का ही भुगतान करना होगा। ब्याज और जुर्माने से छूट होगी। इस तिथि के बाद योजना का लाभ उठाने वालों को करदाताओं को कुछ अतिरिक्त कर राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। योजना 30 जून 2020 तक खुली रहेगी।

श्रीमती सीतारमण ने पिछले साल सितंबर में कंपनी कर में भी भारी कटौती का तोहफा कंपनियों को दिया। कंपनी कर में करीब 10 प्रतिशत की कटौती करने से सरकारी खजाने को 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया। यही वजह है कि 2019-20 का राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत के बजट अनुमान से बढ़कर 3.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान पर पहुंच गया।

राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत

नये वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2020-21 का कुल बजट 30 लाख 42 हजार 230 करोड़ रुपये का है जिसमें कर राजस्व प्राप्तियां 20 लाख 20 हजार 926 करोड़ रुपये, उधार एवं अन्य प्राप्तियों से 10 लाख 21 हजार 304 करोड़ रुपये प्राप्त करने का बजट अनुमान रखा गया है। बजट में राजस्व घाटा 2019-20 के बजट अनुमान 2.3 प्रतिशत के मुकाबले मामूली बढ़कर 2.4 प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान लगाया गया है जबकि 2020-21 में इसके 2.7 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। ■

केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया। 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना हैं।

केन्द्रीय बजट 2020–21 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

बजट के तीन प्रमुख भाग

महत्वाकांक्षी भारत - भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर हो, ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सके।

सभी के लिए आर्थिक विकास - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।'

जिम्मेदार समाज - मानवीय और सहृदय, अंत्योदय, आस्था का आधार।

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन

- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास हेतु 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन।
- कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।

कृषि ऋण

- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव।
- नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना।
- जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्ताव।

नीली अर्थव्यवस्था

- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।
- 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य।

किसान रेल

- सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव
- दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव।
- एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन डिब्बे लगाने का प्रस्ताव।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस सेवा का संचालन।
- पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना।

पीएम–कुसुम का विस्तार

- योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद।
- अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद करना।
- किसानों को अपनी प्रति या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की योजना।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना** – गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ 0.5 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया।

वेलनेस, जल एवं स्वच्छता

- समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जय) के लिए 6400 करोड़ रुपये (69,000 करोड़ रुपये में से) का आवंटन।
- जन औषधि केन्द्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी।
- 'टीबी हारेगा देश जीतेगा' अभियान शुरू किया गया – वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।
- जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये मंजूर।
- वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन।
- ओडीएफ से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए 'ओडीएफ-प्लस' के लिए प्रतिबद्धता।

शिक्षा एवं कौशल

- वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
- पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक, इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।

उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश

- उद्योग और वाणिज्य के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित।
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा।
- भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा।
- ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना 'निर्विक' शुरू की जाएगी।

अवसंरचना

- अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन

- 31 दिसंबर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं लांच की गई।
- विकास के चरण और आकार के आधार पर 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा।
- रोजगार सृजन, कौशल और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

राजमार्ग

राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा, इसमें शामिल हैं:

- पहुंच नियंत्रण राजमार्ग- 2500 किलोमीटर
- आर्थिक गलियारा- 9000 किलोमीटर
- तटीय और भूमि पत्तन सड़कें- 2000 किलोमीटर
- रणनीतिक राजमार्ग- 2000 किलोमीटर
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएंगे।
- चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी।
- 6000 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव।

भारतीय रेल

- रेल पटरियां के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी।
- 4 स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन।

हवाई अड्डा

- उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा।
- इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद।

विद्युत

- स्मार्ट मीटर को बढ़ावा।
- बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय।

ऊर्जा

- 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव।

नई अर्थव्यवस्था

- निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द ही लाई जाएगी।
- भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा।
- 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

स्टार्ट–अप्स के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय

- आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।
- क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।

जिम्मेदार समाज

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के

लिए 35,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।

- महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।
- अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

संस्कृति और पर्यटन

- पर्यटन संवर्द्धन के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- वर्ष 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य हेतु 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख का विकास

- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सार्वजनिक बैंकों में सुधार

- 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया।
- 3,50,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी गई।
- जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीडीसी) ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अनुमति दी।

एमएसएमई का निर्यात संवर्धन

- भेषज, मोटर वाहन पुर्जे तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा 1000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि के लिए सहायता।

विनिवेश

- सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।

प्रत्यक्ष कर

- विकास को गति प्रदान करने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया, अनुपालन सरल बनाया गया और मुकदमेंबाजी कम हुई।

व्यक्तिगत आय कर

- मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत।
- नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आय कर शासन प्रस्तावित।

कर योग्य आय के स्लैब (रुपये)	मौजूदा कर दरें	नई कर दरें
0 से 2.5 लाख	छूट	छूट
2.5 से -5 लाख	5%	5%
5 से 7.5 लाख	20%	10%
7.5 से 10 लाख	20%	15%
10 से 12.5 लाख	30%	20%
12.5 से 15 लाख	30%	25%
15 लाख से ऊपर	30%	30%

- मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।

कॉरपोरेट कर

- 15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।
- भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए

- व्यय के संशोधित अनुमान- 26.99 लाख करोड़ रुपये।
- प्राप्तियों के संभावित अनुमान- 19.32 लाख करोड़ रुपये।

वर्ष 2020–21 के लिए

- जीडीपी की मामूली वृद्धि 10 प्रतिशत अनुमानित है।
- प्राप्ति- 22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित।
- व्यय- 30.42 लाख करोड़ रुपये।
- संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान। इसमें दो प्रमुख कारक हैं।
- वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 बजट अनुमान के लिए 3 प्रतिशत। ■

समृद्ध नए दशक की नींव रखी गई: नरेन्द्र मोदी

कृषि, बुनियादी ढांचे, कपड़ा तथा प्रौद्योगिकी जैसे बड़े रोजगार आधारित क्षेत्रों पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट 2020 को समृद्ध नए दशक की नींव रखनेवाला, भविष्योन्मुखी और कार्रवाई उन्मुख बताया। केंद्रीय बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्होंने कहा, "बजट में घोषित किए गए नए सुधार न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के आर्थिक सशक्तीकरण का लक्ष्य भी रखता है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "इस बजट में नए दशक में अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार सृजन पर ध्यान

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाले कृषि, बुनियादी ढांचे, कपड़ा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट की 16 सूत्री कार्ययोजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन बढ़ाने के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाता है, जहां खेती के पारंपरिक तरीकों के अलावा बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन में मूल्यवर्धन पर भी जोर दिया गया है जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।"

कपड़ा क्षेत्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में तकनीकी मशीनों के इस्तेमाल का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कच्चे माल के शुल्क संरचना में सुधारों की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले 3 दशकों से इसमें सुधार की मांग की जा रही थी।'

स्वास्थ्य क्षेत्र

श्री मोदी ने कहा, "आयुष्मान भारत कार्यक्रम ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार किया है। इसने देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता के साथ-साथ अधिक मानव संसाधनों के लिए गुंजाइश भी बनायी है और सरकार ने इस दिशा में कई फैसले लिए हैं।"

प्रौद्योगिकी क्षेत्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष उपाय किए हैं। उन्होंने कहा, "हमने स्मार्ट शहरों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के विनिर्माण, डेटा सेंटर पार्क, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नीतिगत पहल की हैं। इसके साथ ही भारत वैश्विक मूल्य शृंखला का एक अभिन्न अंग बन जाएगा।"

बजट में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाले कृषि, बुनियादी ढांचे, कपड़ा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट की 16 सूत्री कार्ययोजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन बढ़ाने के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि बजट में डिग्री पाठ्यक्रम में प्रशिक्षुता को शामिल किए जाने, स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रमों जैसे नए और अभिनव पहलों के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों और निर्यात क्षेत्र को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताते हुए कहा कि बजट में लघु उद्योगों के वित्तपोषण के साथ निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अवसंरचना: 6500 से अधिक परियोजनाओं में 100 लाख करोड़ से अधिक का निवेश

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आधुनिक भारत को आधुनिक अवसंरचना की आवश्यकता है और यह क्षेत्र एक बड़ा रोजगार उत्पादक है।

उन्होंने कहा '6500 से अधिक परियोजनाओं में 100 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है और यह एक व्यापक रोजगार सृजन क्षमता का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति व्यापार, उद्योग और रोजगार में भी सहायता करेगी।'

उन्होंने कहा, '100 नए हवाई अड्डों को विकसित करने की घोषणा देश में पर्यटन को बढ़ावा देगी और इसके साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए भी बड़ी संभावना पैदा होगी।'

निवेश में वृद्धि

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए है जो कि रोजगार के लिए एक बड़ा वाहक है। उन्होंने कहा, 'बॉण्ड मार्केट को सुदृढ़ बनाने और अवसंरचना परियोजनाओं के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार लाभांश वितरण कर की समाप्ति के बाद कम्पनियों के पास आगे के निवेश के लिए 25,000 करोड़ रुपये रहेंगे।'

उन्होंने कहा, 'एफडीआई आकर्षित करने के लिए भी कई कर रियायतों की घोषणा की गई।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'ऐसे ही कर लाभ स्टार्ट-अप और रियल स्टेट सेक्टर को भी उपलब्ध कराए गए।'

कराधान में विश्वास पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे वातावरण का निर्माण कर रही है, जहां कोई विवाद नहीं होंगा और आयकर कराधान में भरोसा होगा। उन्होंने कहा, 'कम्पनी कानून में छोटी गलतियों को भी आपराधिक माना जाता था, अब हमने ऐसे कार्यों को गैर-अपराधी मानने का बड़ा फैसला किया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम करदाता चार्टर लॉन्च कर रहे हैं, जो करदाताओं के अधिकारों को सूचीबद्ध करेगी।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि भरोसा बढ़ाने की इसी दिशा में बजट ने घोषणा की है कि अब उन एमएसएमई का लेखा परीक्षण करना अनिवार्य नहीं है जिनका टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये तक है। उन्होंने कहा, 'पहले यह सीमा एक करोड़ रुपये तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।'

वर्तमान में देश के युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसमें प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी अब बैंकों, रेलवे या किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए एक ऑनलाइन कॉमन परीक्षा आयोजित करेगी।

सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त परीक्षा

उन्होंने कहा, 'वर्तमान में देश के युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इसमें प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय नियुक्ति एजेंसी अब बैंकों, रेलवे या किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए एक ऑनलाइन कॉमन परीक्षा आयोजित करेगी।'

न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

प्रधानमंत्री ने कहा कि फेसलेस अपील, सरल आयकर, पीएसयू के विनिवेश में तेजी लाने के प्रयास, समान खरीद प्रणाली, ऑटो इनरोलमेंट जैसे कदमों का उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बजट में ब्राण्डबैंड इंटरनेट के जरिए एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, वेलनेस केन्द्रों और पुलिस थानों को जोड़ने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि यह 'व्यय करने की सुगमता और जीवन की सरलता' में सहायता करेगी। उन्होंने कहा, 'यह ब्राण्डबैंड के जरिए कई सुदूर गांव को भी कनेक्ट करेगी।'

उन्होंने आम बजट 2020 का सार ऐसे बजट के रूप में बताया जो आय और निवेश, मांग एवं उपभोग को सुदृढ़ बढाएगा; ऐसा बजट जो वित्तीय प्रणाली और ऋण प्रवाह में नई प्रेरणा का संचार करेगा। ■

हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार: प्रधानमंत्री

संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया, ''प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था सहित सभी मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध चर्चा होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को वैश्विक संदर्भ में देखें कि भारत इसका फायदा कैसे उठा सकता है।''

उन्होंने बताया कि 'प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।'

श्री जोशी ने बताया कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान 45 विधेयक पेश करने के लिये चिन्हित किये हैं। इनमें से सात वित्तीय विषय से जुड़े हैं तथा दो अध्यादेश से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि बजट सत्र में कुल 39 बैठकें होगी और हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हैं।

बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद एक अंतराल के बाद इसका दूसरा हिस्सा 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा। ■

प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित है यह आम बजट: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 1 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट 2020-21 का हार्दिक स्वागत किया और कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान के कल्याण हेतु केन्द्रित और प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट है।

ऐसे सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी व सर्व-समावेशी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को अपनी ओर से पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। संसद में प्रस्तुत किया गया आम बजट 2020-21 'न्यू इंडिया' के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को चरितार्थ करने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास' के मंत्र से प्रेरित केंद्रीय बजट 2020 एक नए और विकसित भारत की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तनकारी और सर्वांगीण बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट मध्यम आय वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की गति देने वाला बजट है। सबके लिए घर, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए सब्सिडी, आयकर में छूट, SC/ST समुदाय के विकास के लिए धन का आवंटन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की घोषणा मध्यम वर्ग को सशक्त करने की दिशा में उठाया गए ठोस कदम हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के प्रति कृतसंकल्पित है और पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिखाया है। आम बजट 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के न्यू इंडिया की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करता है। इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का यह पहला बजट है जो देश की आशाओं, आकांक्षाओं और जनता के विश्वास को परिलक्षित करता है। बजट 2020 में तीन विषयों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है और वे तीन विषय हैं उम्मीदों का भारत, इकॉनोमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज।

उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, वंचित, शोषित, किसानों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित बजट है। यह बजट विकास को गति और रोजगार का सृजन करने वाला बजट है जिसमें हर सेक्टर के डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया है जो देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाने वाला है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में किसानों का विशेष ख़याल रखा गया है। इस बजट में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार ने 16 सूत्रीय फ़ॉर्मूले का ऐलान किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 100 लाख करोड़ रुपये, परिवहन संरचना फंड के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए परिव्यय फंड के रूप में 99,300 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69000 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति और ओबीसी के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 53,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, जो दर्शाता है कि सरकार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किस तरह समर्पित भाव से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के हर गरीब को उनका अपना मकान देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस दिशा में हमने अच्छी प्रगति हासिल की है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के माध्यम से पहली बार घर खरीद रहे व्यक्ति को 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी देना तय किया है।

श्री नड्डा ने कहा कि आम बजट 2020 व्यक्तिगत करदाताओं के लिए विशेष राहत देने वाला है। पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा जो एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इस आम बजट में बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये लाख कर दिया गया है जिससे जमाकर्ता को अब पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह मध्यम वर्ग के लिए बहुत राहत भरा कदम

शेष पृष्ठ 15 पर...

किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजटः अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 1 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आम बजट 2020-21 का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले ऐसे सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री शाह ने कहा कि यह देश के जन-जन की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक सर्वांगीण बजट है जो विकास को गति देगा और कई सेक्टरों में रोजगार सृजित करेगा। आज के बजट ने यह पुनः सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के गरीबों, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग, युवाओं और महिलाओं के सपनों को समर्पित सरकार है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बजट में किसानों का ख़ास ख़याल रखा गया है। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने 16 एक्शन प्लान अपने हाथों में लिया है। पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिये सोलर पंप मुहैया कराये जायेंगे। साथ ही विलेज कोल्ड स्टोरेज, धन्य लक्ष्मी योजना, फिशरीज और बागवानी में सुधार जैसी कई योजनाओं के जरिये किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम मोदी सरकार द्वारा उठाये गए हैं।

उन्होंने कहा कि किसान रेल और किसान उड़ान योजना के द्वारा हमारे किसान भाई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ेंगे और उनके उत्पाद बिना सड़े-गले सही वक्त पर बेहतर दाम में बिक पाएंगे। यह योजना विशेष रूप से फल व सब्जी उत्पादनकर्ता खासकर हमारे आदिवासी और उत्तर पूर्व के किसानों को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही, यह बजट देश के अन्नदाता किसान को सिंचाई और अनाज भंडारण के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ उनके उत्पाद का उचित दाम उपलब्ध कराकर किसान की आय दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बजट में व्यवसायी कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने, बैंकिंग प्रणाली के सरलीकरण और मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विनिवेश को भी बढ़ावा देने वाले प्रभावी कदम उठाये हैं, जिससे देश में व्यवसाय का माहौल और अधिक अच्छा होगा और भारत तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा।

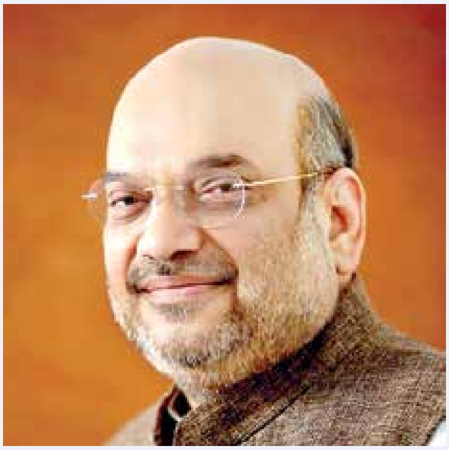

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के करदाताओं को आय कर में एक बड़ी और अभूतपूर्व राहत देने का काम किया है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग के वेतनभोगी करदाताओं को न सिर्फ कम कर देना पड़ेगा, बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण से उनको राहत भी मिलेगी। बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है अर्थात् बैंक के डूबने की स्थिति में भी डिपॉजिटर को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश में मूलभूत ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ के आवंटन से देश में विश्वस्तरीय हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो इत्यादि बन पाएंगे जिससे न सिर्फ आम-जन का जीवन बेहतर होगा बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण बल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 6,000 किलोमीटर हाईवे, 9,000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस वे के साथ-साथ रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा न केवल देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगी, बल्कि भारी मात्रा में रोजगार का भी सृजन करेगी।

श्री शाह ने कहा कि अपने स्वस्थ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए मोदी जी ने इस बजट में आयुष्मान भारत को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना के कवरेज सहित टियर II और टियर III जैसे शहरों में पीपीपी मॉडल द्वारा नए अस्पतालों को जोड़ने का सरहानीय कदम उठाया है। इससे न सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जन-औषधि केंद्रों को हर जिले में शुरू करने की कवायद जन-साधारण को बहुत बड़ी राहत देगी।

गृह मंत्री ने कहा कि सबको घर, सबको बिजली, सबको शौचालय,

सबको गैस, सबको स्वास्थ्य सुविधा जैसे अभियानों को आगे ले जाते हुए मोदी सरकार के सबको नल द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के संकल्प का मैं स्वागत करता हूं। इस योजना में 3.60 लाख करोड़ का आवंटन मोदी जी की कटिबद्धता को दर्शाता है जिससे देश के आम-जन का जीवन व स्वास्थ्य बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान रख कर समाज के उपेक्षित वर्ग के विकास व उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुनः दर्शाया है।

श्री शाह ने कहा कि बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर 28,600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अच्छे नतीजे मिले हैं। प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 94.83% जबकि हायर सेकंडरी एजुकेशन में भी लड़कियां आगे हो गई हैं। लगभग 98% लड़कियां नर्सरी स्तर पर स्कूल जा रही हैं जो बदलते भारत का परिचायक है। 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं। विशेषकर 35 हजार करोड़ रुपये पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करने का मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है, यह वाकई एक काबिले तारीफ कदम है।

गृह मंत्री ने कहा कि देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाये गए हैं और इसके लिए 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पांच आर्कियोलॉजी साइट्स हस्तिनापुर (यूपी), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात), आदिचेल्लनूर (तमिलनाडु), राखीगढ़ी (हरियाणा) को आइकोनिक साइट्स बनाने का निर्णय लिया गया है जो टूरिज्म सेक्टर को और बूस्ट करेगा। लोथल में मेरीटाइम म्यूजियम और रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का निर्णय भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। देश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार ने 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि घरेलू मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। निर्यातकों को सहायता देने के लिए निर्भीक (NIRVIK) नाम से योजना शुरू किये जाने का निर्णय भारत को प्रमुख निर्यातक देशों की कतार में खड़ा करेगा। इसमें उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम मिलेगा और क्लेम सेटलमेंट तेजी से होगा।

उन्होंने कहा कि हर जिले को एक्सपोर्ट हब के तौर पर डेवलप करने के फैसले से विकास के नए द्वार खुलेंगे। सरकारी ई-मार्केटप्लेस के पास एसएमईएस के लिए काफी मौके होंगे। एफवाई -21 में इंडस्ट्री और कॉमर्स के विकास के लिए 27,300 करोड़ दिए जा रहे हैं। टैक्सटाइल उद्योग के लिए भी लगभग 1,800 करोड़ रुपये के पैकेज से शुरू की जाने वाली 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन' योजना भारी मात्रा में रोजगार सृजित करेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि आम बजट 2019 शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के जन-जन की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरी उतरी है और आगे भी इसी समर्पण भाव से जन-जन के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। ■

पृष्ठ 13 का शेष

है। ग्रामीण परिवेश में जहां भारत की अधिकतम जनसंख्या रहती है, वहां सरकार ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए तथा स्वास्थ्य, पानी, आवास, सड़क आदि की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम स्वागत करते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के लिए इस बजट में कई प्रकार की पहल की गई है। आदरणीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों महिला, किसान, युवा और गरीब के लिए आवश्यक प्रावधान किये गए हैं और कई नई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी की है जिसका हम अभिनंदन करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस बजट में पर्यावरण पर भी फोकस किया गया है। स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए 4,000 करोड़ रुपये का खर्च किये जाने का निर्णय शुद्ध पर्यावरण की दिशा में उठाया गया यकीनन एक बेहतर कदम है।

श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 30,757 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,985 करोड़ का फंड दिया है। यह बताता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए कितना संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत लगातार दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत 2022 में जी-20 की मेजबानी करेगा। यह अपने आप में देश को गौरवान्वित करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। ■

बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी: राजनाथ सिंह

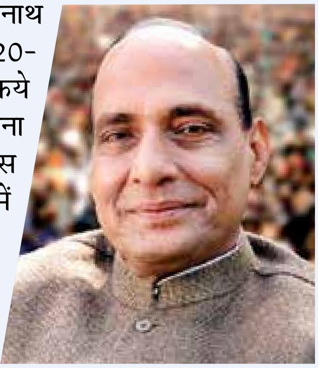

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विकास को बढ़ायेगा और अर्थव्यवस्था में मांग फिर से पैदा करेगा।

श्री सिंह ने कहा कि यह बजट न केवल निवेश अनुकूल है बल्कि यह किसानों की आय को दोगुना करने और भारतीय उद्योगों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

रक्षा मंत्री ने कहा, ''वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किये गये नये दशक का पहला बजट नये और आत्मविश्वासी भारत की रूपरेखा पेश करता है। यह एक आशाजनक, सक्रिय और प्रगतिशील बजट है जो आने वाले वर्षों में देश को और समृद्ध बनाएगा।''

उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण और विकास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित है, इसमे किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीतारमण द्वारा घोषित कदमों से निश्चित रूप से विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

श्री सिंह ने कहा, ''बजट में निवेशकों, करदाताओं और पूंजी सृजित करने वालों को कर उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का आश्वासन देकर निश्चितता का एक माहौल बनाने का वादा भी किया गया है।'' उन्होंने कहा, ''इस वर्ष बजट में पेश किए गए नए कर सुधार अत्यंत प्रगतिशील, साहसिक और प्रकृति से अभूतपूर्व हैं। नई कर प्रणाली से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह एक कुशल कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।''

रक्षा मंत्री ने श्रीमती सीतारमण को नई तकनीकों जैसे क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप के प्रस्ताव के लिए भी बधाई दी।

श्री सिंह ने कहा कि बजट प्रस्तावों ने 2024-25 तक पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशक्त रूप से एक नींव रखी है। उन्होंने कहा, ''लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए देश को एक उत्कृष्ट बजट देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इसमें हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया गया है।''

बजट अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने वाला: नितिन गडकरी

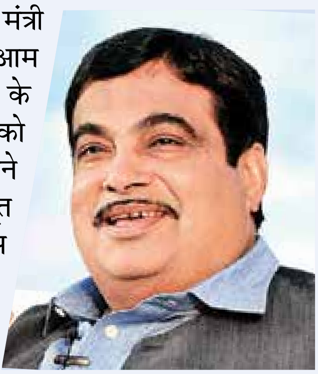

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आम बजट को प्रधानमंत्री के '5 ट्रिलियन' डॉलर के सपने को आधार देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा। इस बजट से अब देश में एक्सप्रेस हाईवे नेटवर्क शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा, "विकास का एक नया युग यहां से शुरू होता है। बजट 91 हजार करोड़ का है, जिससे साफ होता है कि 10.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।"

श्री गडकरी ने कहा कि बजट से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। रोजगार सृजन होगा। बजट में 100 लाख करोड़ रुपये के छह हजार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इससे रोजगार का बड़े स्तर पर सृजन होगा। फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।

मजबूत अर्थव्यवस्था को समर्पित: अनुराग ठाकुर

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई टैक्स दरों से हमने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके लोगों की बचत को बढ़ाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि नए दशक की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बजट भारत को समर्पित है। मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास के साथ सब पर विश्वास रखती है। हमें देश के कोने-कोने से तमाम सुझाव आए। पूरी कोशिश की गई कि इस बार का बजट सभी के लिए अच्छा साबित हो और इस कोशिश में हम पूरी तरह से सफल साबित हुए हैं।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए धन सृजन महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर 'सबका साथ सबका विकास' विजन के साथ किए गए संबोधन में इस बात को प्रमुखता दी गई थी कि धन सृजन से ही धन का वितरण होगा। केन्द्रीय वित्त तथा कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी को संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 में ऐसी नीतियों की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया गया, जो भारत में धन सृजन को तेजी देगी और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था विकास की ऊंचाई पर चलेगी।

आर्थिक समीक्षा के विषय बाजार को सक्षम बनाने, व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत करने के ईर्द-गिर्द हैं। आर्थिक समीक्षा में संतुलित आशावादी दृष्टिकोण रखा गया है और आर्थिक सोच तथा नीति निर्माण की दृष्टि से बाजार अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभों के बारे में संदेह को विराम देने का प्रयास किया गया।

धन सृजन की भारत की समृद्ध परम्परा

आर्थिक समीक्षा में ईमानदारी से धन सृजन को आर्थिक गतिविधि का मूल मानते हुए और भारत के 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के महत्व पर बल देते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र, थीरूवलुवर के थिरूकूरल तथा ऐडम स्मिथ के ऐन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस जैसे शास्त्रीय पुस्तकों का उद्धहरण दिया गया है।

इन शास्त्रीय पुस्तकों के माध्यम से आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि धन सृजन का विचार भारत की पुरानी और समृद्ध परम्परा में समाहित है। तीन चौथाई से अधिक ज्ञात आर्थिक इतिहास से वैश्विक रूप से भारत मजबूत आर्थिक शक्ति है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि यह प्रभुत्व केवल एकाएक होने वाला उदाहरण नहीं है।

बाजार के अदृश्य हाथ

वैश्विक अर्थव्यस्था में भारत के ऐतिहासिक प्रभुत्व की चर्चा करते हुए समीक्षा में बाजार में खुलापन लाने के महत्व पर बल दिया गया ताकि धन सृजन हो और बढ़े हुए निवेश के माध्यम से आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिले। समीक्षा के अनुसार बाजार के अदृश्य हाथ और अदृश्य विश्वास के कारण अतीत में भारत का दबदबा रहा है। समीक्षा में इन दोनों बातों का समकालीन साक्ष्य पेश किए गए हैं। इन तथ्यों ने उदारीकरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को ऊंचाई की ओर लौटने में मदद की।

समीक्षा में धन सृजन की परिकल्पना प्राचीन भारतीय परम्परा तथा समकालीन साक्ष्य के मिश्रण के रूप में प्रस्तुत की गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता बढ़ाने के लिए फिनटेक के उपयोग का सुझाव दिया गया है। समीक्षा में अर्थव्यवस्था संचालन में पुराने तथा नये तरीकों का मिश्रण ठीक उसी तरह है जिस तरह आज देश में सौ रुपये का नए और पुराने दोनों नोट चल रहे हैं।

धन सृजन को बढ़ाने के उपाय

आर्थिक समीक्षा में धन सृजन को बढ़ाने के अनेक उपायों को चिन्हित किया गया है। ये उपाय हैं:

- जमीनी स्तर पर उद्यमिता जैसी कि भारत के जिलों में नई फर्म बनाने में उद्यमिता दिखी है।
- व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना ताकि मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने वाली नीतियों की जगह धन सृजन के लिए स्पर्धी बाजार की शक्ति उभरे और निजी निवेश को समर्थन मिले।
- सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बाजार की अनदेखी करने वाली नीतियों की समाप्ति, जहां ऐसी नीतियां आवश्यक नहीं है।
- श्रम प्रोत्साहन निर्यात पर फोकस करने के लिए और व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन के लिए 'एसेम्बल इन इंडिया' तथा 'मेक इन इंडिया' को एकीकृत करना।
- बैंकिंग क्षेत्र का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में बढ़ाना और बैंकिंग क्षेत्र की मंद सेहत का पता लगाना।
- दक्षता बढ़ाने के लिए निजीकरण का उपयोग। आर्थिक समीक्षा में सावधानीपूर्वक यह साक्ष्य प्रदान किया गया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान पर भरोसा किया जा सकता है। ■

संपन्न हुआ ऐतिहासिक बोडो समझौता

50 वर्ष पुरानी थी यह समस्या

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 50 वर्षों से चले आ रहे बोडो मुद्दे के समाधान के लिये 27 जनवरी को समझौता किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री कहा कि जिस समस्या के कारण करीब 4 हजार लोगों की जानें गईं, आज उसका एक स्थाई एवं सफल निदान हो गया है।

इस समझौते के बाद 1500 से अधिक हथियारधारी सदस्य हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। समझौते में भारत सरकार और राज्य सरकार विशेष विकास पैकेज द्वारा 1500 करोड़ रु. और असम में बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करना शामिल है। इसके अलावा बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।

यह ऐतिहासिक समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उत्तर पूर्व की प्रगति और वहां के लोगों के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास में व्यापक सुधार किया है। श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ और यह समझौता सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है, क्योंकि सारे बोडो संगठन समझौते में शामिल हैं।

उनका कहना था कि पहले उत्तर पूर्व के राज्य अपने को अलग थलग महसूस करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि हर हफ्ते या पंद्रह दिन में केंद्र का एक मंत्री पूर्वोत्तर राज्य का दौरा कर वहां के मूलभूत सरंचना की समीक्षा कर विकास की नई इबारत लिखें। मोदी जी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष संदर्भ में 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' नीति के अंतर्गत त्रिपुरा में

पिछले अगस्त एनएलएफटी के 88 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। 16 जनवरी 2020 को हुए ब्रू-रियांग समझौते पर हस्ताक्षर करने से लंबे समय से चली आ रही मानवीय समस्या का हल निकला और पिछले सप्ताह 644 काडर असम सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर देश की मुख्यधारा में शामिल हुए। आज का बोडो समझौता इस कड़ी में चौथा बड़ा कदम है।

पूर्व में वर्ष 1993 और 2003 के समझौतों से संतुष्ट न होने के कारण बोडो द्वारा और अधिक शक्तियों की मांग लगातार की जाती रही और असम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखते हुए बोडो संगठनों के साथ उनकी मांगों के लिए एक व्यापक और अंतिम समाधान के लिए बातचीत की गई। मोदी सरकार के सत्ता में आने के

यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जनवरी को हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "शांति, सद्भाव और एकजुटता की एक नई सुबह में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है। बोडो समूहों के साथ किया गया यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडो समझौता आज कई कारणों से अहमियत रखता है। यह सफलतापूर्वक एक फ्रेमवर्क के तहत अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाता है। जो लोग पहले सशस्त्र विरोधी समूहों से जुड़े थे, वे अब मुख्यधारा में शामिल होंगे और हमारे देश की प्रगति में योगदान देंगे।

उन्होंने कहा 'बोडो समूहों के साथ समझौता बोडो लोगों की अनूठी संस्कृति को आगे और संरक्षित करते हुए उसे लोकप्रिय बनाएगा। उन्हें विकासोन्मुखी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच मिलेगी। हम बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

बाद अगस्त 2019 से एबीएसयू, एनडीएफबी गुटों और अन्य बोडो संगठनों के साथ दशकों पुराने बोडो आंदोलन को समाप्त करने के लिए व्यापक समाधान तक पहुंचने के लिए गहन विचार-विमर्श भी किया गया।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बीटीसी के क्षेत्र और शक्तियों को बढ़ाने और इसके कामकाज को कारगर बनाना है। इसके साथ बीटीएडी के बाहर रहने वाले बोडो से संबंधित मुद्दों का समाधान तथा बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना भी है। समझौते के अन्य बिंदुओं में आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए विधायी सुरक्षा प्रदान करना और जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ एनडीएफबी गुटों के सदस्यों का पुनर्वास करना भी शामिल है।

समझौते से संविधान में छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है जो बहुसंख्यक गैर-आदिवासी आबादी कि बीटीएडी से सटे गांवों को शामिल करने और बहुसंख्यक आदिवासी आबादी की जांच करने का काम करेगा।

असम सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीटीएडी के बाहर बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो-कचारी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। असम सरकार बोडो भाषा को राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी और बोडो माध्यम स्कूलों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना करेगी।

वर्तमान समझौते के तहत एनडीएफबी गुट हिंसा का रास्ता छोड़ने के साथ साथ आत्मसमर्पण करेंगे और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने के भीतर अपने सशस्त्र संगठनों को खत्म कर देंगे। भारत और असम सरकार इस संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार एनडीएफबी (पी), एनडीएफबी (आरडी) और एनडीएफबी (एस) के लगभग 1500 से अधिक कैडरों के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी। ■

जनवरी, 2020 के लिए 1,10,828 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रह

जनवरी 2020 में संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व रुपये 1,10,828 करोड़ है जिसमें से सीजीएसटी रुपये 20,944 करोड़, एसजीएसटी रुपये 28,224 करोड़ (आयातों पर संग्रहित रुपये 23,481 करोड़) और सेस रुपये 8,637 करोड़ (आयातों पर संग्रहित रुपये 824 करोड़) है। 31 जनवरी, 2020 तक दिसम्बर महीने के लिए फाइल किए गए जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 83 लाख (अनंतिम) है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी को रुपये 24,730 करोड़ और आईजीएसटी से एसजीएसटी को रुपये 18,199 करोड़ का निपटान किया है। जनवरी 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए रुपये 45,674 करोड़ और एसजीएसटी के लिए रुपये 46,433 करोड़ है। घरेलू कारोबार से जनवरी 2020 के दौरान जीएसटी राजस्वों ने जनवरी 2019 के राजस्व की तुलना में 12 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की है। ■

भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां

- भारत और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4% की औसत वृद्धि रही।
- भारत का पत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009-14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।
- केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7% (मार्च 2019) पर, जो मार्च 2014 में 52.2% था।
- प्रौद्योगिकी का प्रसार (एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायो इनफॉर्मेटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमतता)
- भारत में उत्पादक आयु समूह में अब तक के सर्वाधिक लोग मौजूद।
- जीएसटी ने व्यवस्था की तमाम बाधाओं को दूर किया है।

'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट का गठन

'स्वतंत्र ट्रस्ट' अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सभी निर्णय लेगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की निगरानी के लिए ट्रस्ट की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, 'उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर मेरी सरकार ने आज 'श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ट्रस्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का अनुरोध किया था और राज्य सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार किया।

उन्होंने कहा कि हम सभी भगवान राम और अयोध्या से जुड़े ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को जानते हैं। यह भारतीय लोकाचार, भाव, आदर्श और संस्कृति में है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'भव्य राम मंदिर के निर्माण तथा रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि लगभग 67.703 एकड़ अधिग्रहित भूमि नवगठित श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को हस्तांतरित की जाएगी।'

प्रधानमंत्री ने अयोध्या मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद शांति और सद्भाव बनाए रखने में देश द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की सराहना की। उन्होंने इस बात को एक अलग ट्वीट में कहा, 'भारत की जनता ने लोकतांत्रिक तौर-तरीकों तथा प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय विश्वास दिखाया। मैं भारत की 130 करोड़ जनता का नमन करता हूं।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। यह भारत का लोकाचार है। हम प्रत्येक भारतीय को प्रसन्न और स्वस्थ देखना चाहते हैं। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' से निर्देशित होकर हम प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइये हम सब मिलकर भव्य राम मंदिर निर्माण की दिशा में काम करें।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में होंगे 15 ट्रस्टी

एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जायेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की घोषणा करने के बाद उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का यह दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है।

श्री शाह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि "भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूं।"

श्री शाह ने कहा कि "सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अनेक अनेक बधाई देता हूं।"

उन्होंने कहा, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे।' ■

भाजपा का मत-प्रतिशत बढ़ा

दिल्ली विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलीं। जबकि कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल सकी।

आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में करीब 53.57 प्रतिशत मत हासिल किए, वहीं भाजपा को 38.51 फीसदी वोट मिले। भाजपा के सहयोगी दल जदयू एवं लोजपा को क्रमशः 0.91 फीसदी व 0.35 फीसदी मत मिले। इस प्रकार दिल्ली विधान सभा चुनाव में राजग को 39.77 फीसदी वोट मिले। कांग्रेस को 4.26 फीसदी मत से संतोष करना पड़ा। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में 62.59 फीसदी मतदान हुए जबकि 2015 में 67.47 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था। ध्यातव्य है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 8 फरवरी को संपन्न हुए थे और 11 फरवरी को चुनाव परिणाम आए।

विदित हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा शून्य था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54.3 फीसदी और भाजपा को 32.3 फीसदी मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9.7 प्रतिशत मत मिल पाए थे।

भाजपा को हुआ फायदा

आम आदमी पार्टी ने सीटें भले ही सबसे ज्यादा जीतीं पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 6.21 फीसद ज्यादा मत मिले। भाजपा की 5 सीटें भी बढ़ीं।

कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस बार दिल्ली की 70 में से 66 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चार सीटें अपनी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए छोड़ी थी। अपनी लड़ी 66 में से 63 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उसके उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे। कुल मतदान में से पार्टी को 5 फीसदी से भी कम वोट मिले।

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा, "दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई। मैं दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।" श्री केजरीवाल ने श्री मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा दिल्ली के जनादेशों को स्वीकार करती है और वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए श्री नड्डा ने ट्वीट में कहा, ''भाजपा को उम्मीद है कि आप सरकार राष्ट्रीय राजधानी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी की जीत के लिए उन्होंने दिन-रात काम किया।

दिल्ली ने हमें खारिज नहीं किया : मनोज तिवारी

भाजपा, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने विधानसभा चुनाव नतीजों को पार्टी की नैतिक जीत बताया और कहा कि पार्टी का मत प्रतिशत 2015 की तुलना में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने सोच समझकर जनादेश दिया होगा। हमारा मत प्रतिशत 32 से बढ़कर 38 फीसदी हो गया। दिल्ली ने हमें खारिज नहीं किया। हमारे मत प्रतिशत में वृद्धि हमारे लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उम्मीद है कि राष्ट्रीय राजधानी में आरोप-प्रत्यारोप का खेल और काम ज्यादा होगा। उन्होंने श्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी। ■

आत्मिक सुख की आवश्यकता

गतांक का शेष...

दीनदयाल उपाध्याय

एक बार का मुझे अनुभव है। यह पिछली लड़ाई के समय की बात है। उस समय गाड़ी में भीड़ बहुत रहती थी। भीड़ होने के कारण लोग स्टेशन पर टिकट भी नहीं ले पाते थे। कई बार टिकट मिलना भी बंद हो जाता था। लेकिन टिकट मिलना बंद होने के कारण बहुत कम लोग होंगे जो यह सोचेंगे कि चलो आज नहीं तो कल की गाड़ी से चले जाएंगे। नहीं तो ज्यादातर लोगों को तो, किसी भी तरह पहुंचे, पहुंचना ज़रूरी होता है। फिर यह भी आवश्यक नहीं था कि आज टिकट नहीं मिला तो कल मिल ही जाएगा। लोग बिना टिकट लिये गाड़ी में बैठ जाते थे, सोचते थे कि भगवान् जो कुछ करेगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर उन दिनों लोग चला करते थे। इसी तरह गांव का एक किसान बिना टिकट गाड़ी में बैठा था। वह बड़ा चिंतित था। उससे पूछा कि भाई, क्या बात है? तो बोला, 'क्या करें बाबूजी, टिकट नहीं मिला। न मालूम क्या होगा?' वहीं पर एक व्यक्ति और बिना टिकट बैठा था। वह बोल पड़ा, 'तुम्हें ही क्या, टिकट तो मझे भी नहीं मिला।' इसी तरह एक और व्यक्ति बिना टिकट वाला बोल पड़ा। अब सभी जो बिना टिकट वहां बैठे थे, बोलने लगे, 'अगर टिकट नहीं मिला तो क्या सफर करना बंद कर दें? कोई ज़बरदस्ती थोड़े ही है। ज्यादा-से-ज्यादा पैसे अधिक चार्ज कर लेगा और क्या करेगा?' इस प्रकार सभी की हिम्मत बढ़ गई। उनका भय ख़त्म हो गया। एक-दूसरे की चिंता करके समाज में चलना पड़ता है। यदि यह सोच लिया जाए कि पड़ोसी के घर में आग लगी है, अपने घर में थोड़े ही लगी है। उसके घर की आग क्यों बुझाएं? तो इस प्रकार काम नहीं चलता। पड़ोसी का विचार करके चलना ही पड़ता है। यदि पड़ोसी स्वच्छ नहीं है तो उसकी गंदगी से सभी को बीमारी हो सकती है। उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अकेले चलना चाहे तो वह नहीं चल पाएगा। दूसरों के सहारे ही उसको विचार कर चलना होगा। सड़क पर भी दूसरे को देखकर चलना पड़ता है। हम तो यह सोचकर चल रहे हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन सामने से जो आ रहा है, उसके कारण टक्कर हो सकती है।

एक बार इसी तरह का क़िस्सा है। एक सज्जन सड़क पर चले जा रहे थे। अपने ध्यान में मग्न थे। सामने से एक व्यक्ति आ गया। उनकी टक्कर हो गई। उन्होंने उसे डांटकर

हमारा जीवन रेलगाड़ी की तरह है। जैसे ड्राइवर ज़रा सी गड़बड़ कर दे तो कितने ही लोगों का जीवन बरबाद हो जाए। उसी तरह हम भी गड़बड़ कर दें तो हमारा जीवन भी बरबाद हो जाता है।

कहा, 'अंधे हो क्या, देखकर नहीं चलते।' वह व्यक्ति सचमुच अंधा था। अब वह तो अंधा था, लेकिन स्वयं इनको देखकर चलना चाहिए था। एक घटना और याद आती है। अपने एक स्वयंसेवक थे। वे साइकिल बहुत अच्छी चलाते थे। कभी हाथ छोड़कर चलाते थे। कभी पैर ऊपर रखकर चलाते थे। अर्थात सरकस में जितने प्रकार होते हैं, सब उनको आते थे। वह इस प्रकार का सरकस सड़क पर भी करते थे। उनको एकाध बार कहा भी था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़क पर चलते-चलते ना मालूम क्या हो जाए? उसने कहा, 'नहीं, साइकिल तो हमारे लिए ऐसी है जैसे बतख पानी पर चलती है। वैसे ही हम साइकिल पर चलते हैं।' मैंने कहा, 'यह तो ठीक है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए।' एक दिन वह रिक्शा पर बैठकर आ रहे थे और उनकी टूटी हुई साइकिल रिक्शा पर रखी थी। वे कार्यालय में पहुंचे। उनको रिक्शे से उतारा गया। उतारकर उनकी जो मरहम-पट्टी करवानी थी, वह करवाई गई। उनसे पूछा कि क्या हो गया? उन्होंने बताया कि एक जगह टक्कर हो गई। मैंने कहा कि तुम तो साइकिल चलाना अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने बताया कि मैं तो ठीक तरह चला रहा था, लेकिन जो सामने से आ रहा था, उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह टकरा गया। अब यह कभी-कभी हो जाता है। इसलिए जब आप टकराने से बचना चाहते हो तो वह टक्कर एक को बचाने से नहीं बचेगी। वह दोनों की कोशिश से बचेगी। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। झगड़ा भी कभी एक व्यक्ति से नहीं होता। उसमें दो को तो सम्मिलित होना ही है। इसी तरह झगड़ा टालने के लिए भी दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। दोनों व्यक्ति झगड़े को टालना चाहेंगे, तभी वह झगड़ा समाप्त होगा। इसी तरह अकेला कभी नहीं चल सकता।

जब बहुत दिनों के बाद कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, तो उससे गले मिलना होता है। जैसे कि निषाद भगवान् राम के साथ गले मिला था, वैसे ही अगर कोई मिलना चाहे। आप कितना ही हटें, वह आपको छोड़ने के लिए तैयार न हो, तब आप क्या करेंगे? आपको मिलना ही होगा। एक्सीडेंट की कितनी ही घटनाएं घटती रहती हैं। एक के कुशल होने से काम नहीं चलता। दोनों को कुशल होना चाहिए। मृत्यु न जाने कब आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही एक बार की बात है। लुधियाना स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार करते हुए यात्री बैठे थे। एक व्यक्ति का अचानक दिमाग़ ख़राब हो गया। उन्होंने अचानक अपनी तलवार निकाली और जो व्यक्ति उनके पास बैठा था, उसके सीने में भोंक दी। दूसरे को, तीसरे को मारा। कुल छह व्यक्तियों को तलवार से मार दिया। बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़कर हवालात में बंद किया। अगर बाक़ी लोग भी यह सोच

बैठते कि अब ये छह तो गए, इनको कैसे बचाएं, तो वह व्यक्ति और भी नुक़सान कर सकता था। उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए उसे पकड़ा। हमारा यह जीवन कितनी ही दूसरी शक्तियों के ऊपर निर्भर है।

हमारा जीवन रेलगाड़ी की तरह है। जैसे ड्राइवर ज़रा सी गड़बड़ कर दे तो कितने ही लोगों का जीवन बरबाद हो जाए। उसी तरह हम भी गड़बड़ कर दें तो हमारा जीवन भी बरबाद हो जाता है। यह सारा सुख जीवन का इस आधार पर चलता है। यहां तक कि कई बार मन में आता है कि दूसरों के साथ मिलकर बैठने से आनंद आता है। कई बार इनसान मन की बात कहने को इतना लालायित रहता है कि कोई मिले तो झट से उसे सब कुछ बता दिया जाए और यदि कोई नहीं मिलता तो मन परेशान रहता है। कई बार दक्ष में खड़े-खड़े स्वयंसेवक भी आपस में विचार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मन के अंदर से विचार उठता है। वे उसे रोक नहीं सकते।

उनकी हालत ऐसी होती है, जैसी कि एक नाई की हो गई थी। एक नाई था। वह राजा की हजामत बनाने के लिए गया। हजामत बनाते-बनाते एक दिन देखा कि राजा का कान जो है, कुछ कटा हुआ है। अब राजा का कटा हुआ कान देखा। राजा को भी ध्यान आ गया कि वह अपने कटे हुए कान को पगड़ी में छुपाए रखता है, लेकिन अब वह नाई से कैसे छुपाएगा। राजा ने नाई से कहा कि तूने तो मेरा कान देख लिया। लेकिन यदि किसी और को भी तूने यह बात बताई तो मैं तुझे फांसी लगवा दूंगा। नाई ने कहा हुज़ूर, मेरे मुंह से तो यह कभी निकल ही नहीं सकता। समझ लीजिए कि मेरे पेट में गई हुई बात ऐसी होती है, जैसे कुएं में गई वस्तु। आप चिंता मत कीजिए।' अब वहां से तो वह कहकर आ गया। लेकिन इतनी बड़ी बात वह बेचारा किसी से न कहे तो क्या करे? उसका पेट फूलने लगा। वह बात हजम नहीं हो पा रही थी। उसका पेट फूलता ही जा रहा था। वैद्य को दिखाया। उन्होंने सोचा कि पेट ख़राब है। इसको जुलाब दे दिया जाए। परंतु जुलाब देने से पेट की सफाई तो अच्छी हो गई, लेकिन पेट का फूलना बंद नहीं हुआ। बहुत परेशान हुआ। चिंता होने लगी। वहां एक साधू आया। उसने साधू को पेट दिखाया। साधु को लगा कि इसके पेट में कोई बात है। उसने नाई को सुझाव दिया कि तुम फलाने-फलाने जंगल में जाओ। वहां फलाने बांस का पेड़ है। वहां जाकर के गोबर का चौका लगाओ। उसके बाद वहां एक नारियल रखो और दीपक जलाकर मिठाई वगैरह रखकर बताशे, खीर, रोली, चंदन से बांस की पूजा करो। बांस से अपने दिल की सारी बात बता देना। पेट ठीक हो जाएगा। नाई ने वैसा ही किया। बांस को अपने मन की बात बता दी। नाई का पेट ठीक हो गया। अब उस बांस को जब काटा गया, उसकी बांसुरी बनाई गई। उस बांसुरी को जब बजाया गया तो यही स्वर निकलता था कि राजा का कटा कान। आख़िर राजा के कटे कान की बात सभी को पता चल गई। नाई से बात छुपाई नहीं गई। इसी तरह अपना यह पेट कभी कोई बात नहीं छुपा पाता और जब छुपाता है तो फूल जाता है।

यदि हमने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई तो बुरा हाल हो जाता है। कभी-कभी- जब हमारी बात को कोई नहीं सुनता तो हमें बुरा लगता है। बैठक में भी ऐसा ही होता है।

यदि हमने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई तो बुरा हाल हो जाता है। कभी-कभी- जब हमारी बात को कोई नहीं सुनता तो हमें बुरा लगता है। बैठक में भी ऐसा ही होता है। जब कोई सोने लगता है तो ऐसा लगता है कि वह हमारी बात नहीं सुन रहा है। कवि के बारे में कहते हैं कि कभी उससे कहो कि ज़रा कविता सुना दे तो वह बड़ी मनावने करवाता है, संगीतकार से कहो तो वह भी मनावने करवाता है। यदि उसकी इच्छा होगी तो वह मौक़ा ढूंढ़ता रहेगा अपनी रचना सुनाने के लिए। ऐसे ही एक कवि का मुझे मालूम है। उन्होंने मेरे पास आकर अपनी कविता पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी सी कविता पढ़ी। मुझे रस आया या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि मुझे कविता में कोई रस नहीं है। उसके लिए कोई रसज्ञ चाहिए। किंतु फिर एक स्वाभाविक शिष्टाचार के कारण उनकी तारीफ़ कर दी। उन्होंने इस बात को समझा कि कोई बड़ा कद्रदान मिल गया। इसलिए उन्होंने कहा कि यह तो कुछ नहीं है, एक दूसरी सुनिए। मैंने सोचा कि तारीफ़ करके ग़लती कर दी। लेकिन उन्होंने तीसरी, चौथी और बस सुनाते ही गए। वे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं कहता कि मुझे कहीं जाना है तो वे कहते कि नहीं, यह तो सुनिए, क्या दूर की कल्पना इसके अंदर आई है। उनको इसी में आनंद आ रहा था। अब कल्पना कीजिए कि मैं उनकी बात नहीं सुनता तो शायद उनका आनंद किरकिरा हो जाता। इसलिए कवि ने भगवान से प्रार्थना की है कि उसे कोई भी दुःख दे देना, बस एक ही दुःख न देना, और वह यह है कि अरसिकेषुकवित्त निवेदनम शिरिस मा लिख मा लिख मा लिख' कि अ-रसिक जो हैं, जिनको रस नहीं आता, ऐसे व्यक्ति से सामना न हो, जो मेरी कविता न सुन सके। कवि का सबसे बड़ा दुःख यही रहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले, जो उसकी कविता को पसंद न करे या सुननी न चाहे। कवि का सुख भी दूसरे लोगों के ऊपर ही अवलंबित रहता है।

हमारा जो राज्य है, यह कहां से आता है? हम भाषा कहां से सीखते हैं? कहने को तो आदमी कह जाता है कि मेरा गला है, मेरी जीभ है, मैं इन्हीं से बोलना सीखता हूं। लेकिन उसे पता नहीं कि यदि यह समाज न हो तो उसे ज्ञान कहां से आएगा, बोलना कैसे आएगा? उसे चलना कैसे आएगा? जीने का ढंग कैसे आएगा? मनुष्य कितना भी कहे कि यह मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, मैं इसी से चलना सीखता हूं। लेकिन उसकी बात बिल्कुल ग़लत है।

क्रमशः

-पाञ्चजन्य, मई 27, 1961, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ

नहीं रहे पी. परमेश्वरन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ प्रचारक और प्रख्यात विचारक श्री पी. परमेश्वरन का 9 फरवरी, 2020 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री परमेश्वरन, जिन्होंने जनसंघ के दिनों में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के साथ काम किया था, उन्हें 2018 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

श्री परमेश्वरन एक बेहतरीन लेखक होने के साथ ही एक कवि और शोधकर्ता भी थे। वह भारतीय जनसंघ के सचिव (1967-1971) और उपाध्यक्ष (1971-1977) रहे। साथ ही दीनदयाल शोध संस्थान (1977-1982) नई दिल्ली के निदेशक भी थे। 1927 में अलप्पुझा जिले के मुहम्मा में जन्मे श्री परमेश्वरन अपने छात्र जीवन के दौरान ही आरएसएस से जुड़ गए थे। आपातकाल की खिलाफत करने लिए उन्होंने अखिल भारतीय सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरुप उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको 16 महीने जेल में बिताने पड़े। परमेश्वरन ने 1982 में केरलवासियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विचार केंद्र की स्थापना की।

श्री परमेश्वरन ने अपने जन्मस्थान पर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद सेंट बर्चमंस कॉलेज, चंगनाचेरी में अपनी पढ़ाई जारी रखी और यूनिवर्सिटी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम से प्रथम श्रेणी में बीए (ऑनर्स) इतिहास की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बचपन से ही उनका हिंदू धर्म के अध्ययन की ओर बड़ा झुकाव था। वह अधिकांश हिंदू सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ आत्मीयता से जुड़े हुए थे।

प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दीर्घानुभवी सामाजिक कार्यकर्ता पी. परमेश्वरन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि "श्री पी. परमेश्वरन भारत माता के एक प्रतापी और समर्पित पुत्र थे। उनका जीवन भारत के सांस्कृतिक जागरण, आध्यात्मिक उत्थान और गरीब से गरीब लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित था। परमेस्वरन जी के विचार विपुल थे और उनकी लेखनी उत्कृष्ट थी। वह अदम्य थे।

श्री परमेश्वरन के निधन के समाचार से अत्यंत दुःखी प्रधानमंत्री ने कहा कि परमेश्वरन जी एक निर्माता थे, जिन्होंने भारतीय विचार केंद्र, विवेकानंद केंद्र और ऐसे ही अन्य प्रख्यात संस्थानों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ

कई बार चर्चा करने का अवसर मिला और इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं। वह एक श्रेष्ठ बुद्धिजीवी थे।

एक अपूरणीय क्षति: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने इस नेता के निधन पर कहा, "हमारे वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक और पद्म विभूषण श्री पी. परमेश्वरन जी का निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वह भारतीय विचार केंद्र और कई अन्य संस्थानों के संस्थापक थे। उन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रेरित किया।"

परमेश्वरन एक महान समाज सुधारक और एक सच्चे राष्ट्रवादी थे: अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने श्री परमेश्वरन के निधन पर एक ट्वीट कर कहा, "वरिष्ठ प्रचारक और पद्म विभूषण पी. परमेश्वरन जी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुःखी हूं। वह एक महान समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ओम शांति।" उन्होंने कहा कि "परमेश्वरन जी भारतीय विचार केंद्र के निदेशक और विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष थे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके लेखन और विचार अद्वितीय थे। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बहाल करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। " ■

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एमएसएमई की संख्या 15,000 से ऊपर का लक्ष्य: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 फरवरी को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सैन्य प्रदर्शनी (डेफएक्सपो) के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत की इस द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी में ग्लोबल रक्षा निर्माण केन्द्र के रूप में देश की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। डेफएक्सपो, 2020 भारत के सबसे बड़े रक्षा प्रदर्शनी मंच और दुनिया के शीर्ष डेफएक्सपो में से एक बन गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में सभी का डेफएक्सपो के 11वें संस्करण में स्वागत करने में दोगुनी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह लोगों और भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मेक इन इंडिया से न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे भविष्य में रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।'

नए भारत के नए लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए दो बड़े गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। एक तमिलनाडु में और एक अन्य उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे के अंतर्गत लखनऊ के अलावा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट और कानपुर में नोड्स स्थापित किए जाएंगे। भारत में रक्षा सामानों के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए नए लक्ष्य तय किए गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्ष में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एमएसएमई की संख्या 15,000 से ऊपर ले जाना है। आई-डीईएक्स के विचार को बढ़ाने के लिए 200 नए रक्षा स्टार्ट-अप्स शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रयास कम से कम 50 नई टेक्नोलॉजी और उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि देश के प्रमुख उद्योग संगठन रक्षा सामानों के निर्माण के लिए एक साझा मंच बनाएं, ताकि वे रक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विकास और उत्पादन दोनों का लाभ उठा सकें।

भारत सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विशाल अवसर

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का डेफएक्सपो भारत की विशालता, उसकी व्यापकता, उसकी विविधता और दुनिया में उसकी विस्तृत भागीदारी का जीता-जागता सबूत है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में मजबूत भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि यह एक्सपो न सिर्फ रक्षा से जुड़े उद्योग, बल्कि भारत के प्रति दुनिया के विश्वास को भी प्रतिबिंबित करता है। जो लोग रक्षा और अर्थव्यवस्था के बारे में जानते है, वह निश्चित रूप से यह भी जानते होंगे कि भारत सिर्फ बाजार ही नहीं, बल्कि समूची दुनिया के लिए एक विशाल अवसर है।

कल की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करता है रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन

प्रधानमंत्री ने कहा कि डेफएक्सपो की उप विषयवस्तु 'रक्षा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन' कल की चिंताओं और चुनौतियों को दर्शाता है। जैसे-जैसे जीवन टेक्नोलॉजी चलित होता जा रहा है, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां और गंभीर होती जा रही हैं। यह केवल वर्तमान के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में रक्षा बल नई प्रौद्योगिकियां तैयार कर रहे हैं, भारत भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। अनेक प्रतिकृतियां (प्रोटोटाइप) तैयार की जा रही हैं। हमारा उद्देश्य अगले पांच वर्ष के दौरान रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कम से कम 25 उत्पाद विकसित करना है।

अटल बिहारी वाजपेयी का स्वप्न हकीकत में बदला

प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ में चल रहा एक्सपो एक अन्य कारण से भी महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण का स्वप्न देखा था और इसके लिए अनेक कदम उठाए थे।

श्री मोदी ने कहा कि उनकी कल्पना के रास्ते को अपनाते हुए हम अनेक रक्षा उत्पादों के निर्माण में तेजी लाए। हमने 2014 में 217 रक्षा लाइसेंस जारी किए। पिछले पांच वर्षों में यह संख्या 460 पर पहुंच गई। भारत आज आर्टिलरी गनों, विमान वाहकों से लेकर युद्धपोत पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। वैश्विक रक्षा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। पिछले दो वर्षों में भारत ने करीब 17000 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उत्पाद निर्यात किए। अब हमारा लक्ष्य रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में हमारी सरकार ने अनुसंधान और विकास को हमारे राष्ट्र की नीति का एक प्रमुख हिस्सा बना दिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास तथा निर्माण के लिए देश में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।

उपयोगकर्ता और उत्पादक के बीच साझेदारी

प्रधानमंत्री ने कहा कि उपयोगकर्ता और उत्पादक के बीच सहभागिता से राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'रक्षा निर्माण केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी निजी क्षेत्र के साथ समान भागीदारी और साझेदारी होनी चाहिए।' ■

बोडो समझौता असम में नया सवेरा लाएगा: प्रधानमंत्री

एक समय बोडोलैंड के लिए सशस्त्र आंदोलनों का गवाह रहे असम में शांति पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सात फरवरी को कश्मीरी उग्रवादियों, पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित संगठनों और नक्सलियों से हथियार छोड़ने तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने और "जीवन का जश्न" मनाने की अपील की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के समारोह में शिरकत की।

श्री मोदी ने कहा, "आज का दिन असम सहित पूरे पूर्वोत्तर के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरूआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा का स्वागत करने का अवसर है। आज का दिन यह संकल्प लेने का दिन है कि विकास और विश्वास हमारा मुख्य आधार बना रहेगा और हम इसे और मजबूत बनाएंगे। हिंसा का अंधेरा हमें फिर से ना घेर ले। आइये, हम शांतिपूर्ण असम और एक नए दृढ़ भारत का स्वागत करें।"

27 जनवरी, 2020 को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रधानमंत्री की यह पूर्वोत्तर की पहली यात्रा है।

बोडो समझौता: सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की छाया

प्रधानमंत्री ने बोडो समझौते में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी), बीटीसी के प्रमुख और असम के राज्यपाल श्री हगरामा माहीलारे की सराहना की। उन्होंने कहा कि बोडो समझौता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। श्री मोदी ने कहा, "गांधी जी कहा करते थे कि जो भी अहिंसा के नतीजे होंगे, उन्हें सब स्वीकार करेंगे।"

बोडो समझौते के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र की पूरी जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत बोडो क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) की शक्तियों को बढ़ाया गया है और मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति विजेता है, शांति विजेता है और मानवता विजेता है।

प्रधानमंत्री ने बीटीएडी के कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी के लिए 1500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे बोडो संस्कृति, क्षेत्र और शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा।

बीटीसी और असम सरकार की बढ़ी हुई जिम्मेदारी के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विकास का लक्ष्य केवल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के माध्यम से ही पूरा हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज बोडो क्षेत्र में नई आशाओं, नए सपनों और नई भावनाओं का संचार हुआ है, आप सभी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुझे विश्वास है कि बोडो क्षेत्रीय परिषद यहां उपस्थित सभी समाजों को साथ लेकर विकास के एक नए मॉडल को विकसित करेगा। यह असम और भारत, एक श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाएगा।' प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार असम समझौते के खंड 6 को लागू करना चाहती है और इसके लिए समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।

पूर्वोत्तर की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नया दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाना क्षेत्र की आकांक्षाओं और भावनात्मक मुद्दों को गहराई से समझने के बाद ही संभव हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श और परिचर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढे गए हैं। हमने सभी लोगों को अपना माना और किसी को भी बाहरी नहीं समझा। हम लोगों ने उन लोगों के साथ बातचीत की और उन्हें यह महसूस कराया कि वे भी हमारे अपने हैं। इससे उग्रवाद को कम करने में सहायता मिली। पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद के कारण हजार से अधिक हत्याएं होती थीं, परन्तु आज मोटे तौर पर स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण है।'

पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन है

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले 3-4 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में सड़कों का निर्माण हुआ है जिनकी कुल लम्बाई 3000 किलोमीटर से अधिक है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी दी गई है। पूर्वोत्तर के पूरे रेल नेटवर्क को बड़ी लाइन में बदला गया है। शिक्षा, कौशल और खेल के नए संस्थाओं के जरिए पूर्वोत्तर के युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली और बेंगलुरु में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए नए छात्रावासों का निर्माण किया गया है।' ■

संसद ने नयी सरकार के गठन के बाद कई ऐतिहासिक कानून पारित कर रिकॉर्ड बनायाः रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संसद ने नयी सरकार के गठन के बाद पहले सात महीनों में कई ऐतिहासिक कानून पारित कर रिकॉर्ड बनाया है।

श्री कोविंद ने 31 जनवरी को संशोधित नागरिकता कानून को ऐतिहासिक करार देते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश के निर्माताओं के स्वप्नों को पूरा किया है। भारत ने हमेशा सर्वधर्म समभाव पर विश्वास किया।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वे भारत आ सकते हैं। संसद ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनके विचारों का सम्मान किया है।

राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों की आलोचना की तथा विश्व समुदाय से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान वैसा ही है जैसाकि पहले था।

अनेक ऐतिहासिक कानूनों का निर्माण

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला तीन तलाक विरोधी कानून, देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून, गरीबों की बचत की रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून, गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंट संशोधन कानून, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सज़ा सख्त करने वाला कानून, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून, जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चलते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार की योजनाओं ने हर धर्म, हर क्षेत्र के गरीबों के हित में, समानता के साथ, सहायता व सुविधाएं पहुंचाई हैं और इसलिए देश के लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि देश के लोग खुश हैं कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को सात दशक बाद देश के बाकी हिस्सों के बराबर अधिकार मिले।

पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास, हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा तथा वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश, नए भारत के निर्माण के लिए दिया है।

- एक ऐसा नया भारत, जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं।
- एक ऐसा नया भारत, जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी।
- एक ऐसा नया भारत, जिसका हर क्षेत्र विकास करे, कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के आखिरी छोर तक पहुंचे, तथा
- एक ऐसा नया भारत, जो चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाए और विश्व मंच में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ■

कृषि बजट में पांच गुना की बढ़ोतरी: नरेन्द्र मोदी

सरकार की कल्पना है अधिक निवेश, बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिकतम रोजगार सृजन

लोक सभा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 फरवरी को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का अभिभाषण उम्मीद की भावना पैदा करता है और आने वाले समय में राष्ट्र को आगे ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "उनका संबोधन ऐसे समय में आया है जब हमने सदी के तीसरे दशक में प्रवेश किया है। राष्ट्रपति जी के संबोधन में उम्मीद की भावना है और यह आने वाले समय में देश को आगे ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।"

श्री मोदी ने कहा कि अब देश के लोग इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। वे गति और परिमाण, दृढ़ संकल्प और कड़े निर्णय लेने की क्षमता, संवेदनशीलता और समाधान चाहते हैं। हमारी सरकार ने तेज गति से काम किया है और इसका परिणाम है कि पांच साल में 37 मिलियन लोगों के पास बैंक खाते हैं, 11 मिलियन लोगों के घर में शौचालय हैं, 13 मिलियन लोगों के घरों में रसोई गैस है। आज 2 करोड़ लोगों का सपना है कि उनका अपना घर हो। दिल्ली की 1700 से अधिक अवैध कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों का अपने घर का लंबा इंतजार खत्म हो गया है।

कृषि बजट में पांच गुना वृद्धि हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), फसल बीमा और सिंचाई से संबंधित योजनाएं कई दशकों से लंबित थीं। हमने एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाया और रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए।

प्रधानमंत्री ने कहा, "साढ़े पांच करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हुए; किसानों को साढ़े तेरह करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया गया; 56 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा दावों का निपटारा किया गया।"

श्री मोदी ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में कृषि बजट में पांच गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री-किसान सम्मान योजना अनेक किसानों का जीवन बदल रही है। 45,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है और कई किसानों को इसके कारण लाभ हुआ है। इस योजना में कोई बिचौलिया नहीं हैं और न ही फाइल से जुड़ा कोई अतिरिक्त कार्य है।

किसान की आमदनी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), फसल बीमा और सिंचाई से संबंधित योजनाएं कई दशकों से लंबित थीं। हमने एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाया और रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए।

अधिकतम रोजगार सृजन पर जोर

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाया है। उन्होंने कहा, 'मूल्य वृद्धि भी जांच के दायरे में है और वृहद आर्थिक स्थिरता है।' श्री मोदी ने निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की चर्चा की।

उन्होंने कहा, "स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा कई लोगों के जीवन में समृद्धि लाई है। मुद्रा लाभार्थियों में पर्याप्त संख्या महिलाओं की है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों युवाओं को लाभान्वित करने के लिए 22 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों की मंजूरी दी गई है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार श्रमिक यूनियनों के साथ विचार-विमर्श के बाद श्रम सुधारों पर काम कर रही है।" श्री मोदी ने कहा, "हमारे लिए बुनियादी ढांचा लोगों को उनके सपनों से जोड़ने, उपभोक्ताओं को लोगों की रचनात्मकता से जोड़ने के बारे में आकांक्षाओं और उपलब्धियों का मिश्रण है। बुनियादी ढांचा एक बच्चे को उसके स्कूल, एक किसान को बाजार, एक व्यापारी को अपने ग्राहकों से जोड़ रहा है। यह लोगों को लोगों से जोड़ने के संबंध में है।"

प्रधानमंत्री ने इस विषय पर आगे बढ़ते हुए कहा कि भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने वाली चीजों में से एक अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा है।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में बुनियादी ढांचे का गठन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आर्थिक अवसर लाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने इस क्षेत्र को पारदर्शी बनाया है और संपर्क को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे और इससे विकास, अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ेगा। ■

राज्यसभा

'छोटे शहर नए भारत का आधार'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में 6 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में उड़ान योजना के अंतर्गत 250 मार्ग शुरू किए गए हैं। इससे वायु सम्पर्क वहनीय हो गया है और भारत के 250 छोटे शहरों तक हवाई सम्पर्क पहुंच गया है।

श्री मोदी ने कहा, "आजादी से 2014 तक जहां देश में केवल 65 हवाई अड्डे परिचालन में थे, उनकी संख्या पिछले 5 वर्ष में 100 से अधिक हो गई है। लक्ष्य टियर-2, टियर-3 शहरों में 2024 तक 100 और हवाई अड्डे बढ़ाने का है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन हमें बड़ा सोचकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत पूरी गति और पूरी क्षमता के साथ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का सपना देख रहा है।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए सरकार गांव और शहर के बुनियादी ढांचे, एमएसएमई, कपड़ा, प्रौद्योगिकी और पर्यटन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इन सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मेक इन इंडिया को गति प्रदान करने के लिए कर संरचना सहित सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। ये कदम विनिर्माण के बारे में देश में नए उत्साह को सुनिश्चित करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में विलय नीति के सार्थक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

देश के सबसे आकांक्षी युवा छोटे शहर में रहते हैं जो नए भारत की नींव हैं। आज देश में आधे से अधिक डिजिटल लेनदेन छोटे शहरों में हो रहे हैं। देश में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप्स में से आधे टियर -2, टियर -3 शहरों में हैं। यही कारण है कि हम टीयर -2, टीयर -3 शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सबसे आकांक्षी युवा छोटे शहर में रहते हैं जो नए भारत की नींव हैं। आज देश में आधे से अधिक डिजिटल लेनदेन छोटे शहरों में हो रहे हैं। देश में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप्स में से आधे टियर -2, टियर -3 शहरों में हैं। यही कारण है कि हम टीयर -2, टीयर -3 शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमार्ग और रेल संपर्क में तेजी से सुधार हो रहा है। ■

गंगा शुद्धि का भगीरथ प्रयास

शिव प्रकाश

काशी से 2014 में चुनाव लड़ते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह वक्तव्य कि "ना तो मुझे भेजा है और ना ही मैं आया हूं मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है।" यह उनका गंगा के प्रति समर्पण भाव को ही प्रकट करता है।

गंगा सदियों से भारतीय समाज के मन में अगाध श्रद्धा का विषय रही है। भगीरथ जब उसे भूलोक पर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए लेकर आए तभी से वह आज तक अपने भक्तों का उद्धार करती रही हैं। वह मुक्ति दायिनी हैं, पाप विनाशिनी है, मोक्षदायिनी हैं। इसी श्रद्धा भाव से प्रतिवर्ष करोड़ों लोग उसमें डुबकी लगाकर अपने को पवित्र करते रहे हैं। हरिद्वार एवं प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेलों की संख्या ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह मेले विश्व के लोगों के लिए शोध का विषय एवं अनेकों विश्वविद्यालयों में अपने व्यवस्थापन के लिए अध्ययन के विषय हो गए हैं।

महाकवि तुलसीदास जी ने गंगा को सभी सुखों को प्रदान करने वाली एवं सभी कष्टों को समाप्त करने वाली "गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला" कहकर मां गंगा की विशेषता का वर्णन किया है। भारतीय समाज ने गंगा के इस पवित्र भाव को स्मरण कर देश की समस्त नदियों में गंगा के ही स्वरूप का दर्शन किया है। लाखों वर्षों से मोक्ष की इच्छा रखने वाले ऋषि- मुनियों ने मां गंगा के किनारे अपने आश्रम बनाकर एवं तप करके अपना उद्धार तो किया ही है, साथ ही इसके महत्व को भी द्विगुणित कर दिया है।

मां गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक 5 राज्यों से होते हुए 2510 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। पुण्य सलिला मां गंगा अपनी पवित्रता के साथ-साथ भारत की लगभग 40% जनसंख्या की जीविका का आधार भी हैं। अपने किनारे बसने वाले शहरी एवं ग्रामों की आबादी को जीवन प्रदान करने का कार्य मां गंगा करती है। अपने दोनों ओर एक बड़ा उपजाऊ कृषि क्षेत्र भी गंगा के कारण निर्माण होता है। जिसके सिंचाई का आधार मां गंगा होने के कारण वह मोक्षदायिनी के साथ-साथ जीवनदायिनी भी हो जाती हैं।

अपनी भौतिक सुख-सुविधाओं की इच्छा पूर्ति के कारण मां गंगा पर बनने वाली परियोजनाएं एवं उनके निर्माण के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के कारण सूखते जल स्रोत, गंगा के किनारे के उद्योगों से निकलने वाला जहरीला पानी एवं शहरों से आने वाला मलमूत्र युक्त गंदा पानी आज मां गंगा की निर्मलता एवं अविरलता पर बड़ा संकट है। इस संकट की भयावहता से चिंतित होकर अनेक सामाजिक संगठन, संत महात्मा गंगा रक्षण के लिए समाज जागरण एवं आंदोलनों के माध्यम से सक्रिय हुए।

भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने घोषणा-पत्र में गंगा रक्षा का संकल्प देश के सम्मुख प्रकट किया था। नमामि गंगे मंत्रालय एवं भाजपा संगठन ने नमामि गंगे प्रकल्प के माध्यम से समाज में जागरूकता एवं शासन के प्रयास दोनों ही माध्यम से कार्य किया। पिछली सरकारों की गंगा शुद्धि के प्रयासों के समान असफलता ना मिले, इसका भी प्रयास हुआ। 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि "अगर हम इसे साफ करने में सफल हो गए तो देश की 40 फ़ीसदी आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी।"

प्रयासों की सफलता के लिए नमामि गंगे एकीकृत मिशन, गंगा सफाई का बजट 4 गुना बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपया करना। संपूर्ण बजट केंद्रीय हिस्सेदारी से ही हो जिसके कारण राज्यों के व्यवधान समाप्त हुए।

नगरों से आने वाले जल को शुद्ध करने वाले प्लांट एवं औद्योगिक प्रदूषित पानी को कठोरता से रोकने का कार्य भी हुआ है। कटाव रोकने के लिए वनीकरण का लक्ष्य 30000 हेक्टेयर भूमि पर कराना भी योजना का अंग है। रिड्यूस, रियूज़, रिकवरी का आधार लेकर गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से आने वाले पानी के शोधन का कार्य भी हो रहा है।

समाज के जागरण के लिए मेलों का उपयोग, शिक्षण संस्थानों में जानकारी, गोष्ठियों आदि के माध्यम से नमामि गंगे एवं गंगा समग्र जैसी संस्थाएं सतत् कार्य कर रही हैं। संत महात्माओं के प्रयास अथवा अपने-अपने तरीके से लगी सभी संस्थाओं के कार्य भी सराहनीय हैं।

मोदीजी के नेतृत्व में कानपुर में गंगा किनारे स्थित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सरकारी प्रयासों की समीक्षा की गई। आस्था को अर्थ से जोड़ने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में एवं उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा रक्षा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के बैराज से एवं बलिया से दो यात्राएं 26 जनवरी से प्रारंभ हो रही हैं। क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी बिजनौर एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन पटेल बलिया से सभा को संबोधित कर यात्रा प्रारंभ करेंगी। प्रतिदिन यात्रा में अनेक मंत्री गण एवं जनप्रतिनिधियों सहित समाज की भागीदारी होगी। मोदीजी के मार्गदर्शन में गंगा रक्षण एवं गंगा को अर्थ से जोड़ने का यह प्रयास भागीरथ प्रयास ही है। हम सब भी इस पवित्र कार्य के सहभागी बने। हम गंगा सेवा करें मां गंगा हम सभी को जीवन प्रदान करेगी। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं)

बजट 2020 किसान हितैषी एवं विकासोन्मुख है

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसके लिए यह बजट सक्षम भूमिका प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी विकास दर इस बात की द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी।

इस बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। तीन महत्वपूर्ण भाग बजट की दिशा निर्धारित करते हैं। देश का एक बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदीरी सुनिश्चित करना चाहता है। उसके लिए एसपिरेशनल इंडिया के प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवेश की जनता के जीवन स्तर को ऊपर लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, पानी, मकान एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए; जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान योजना', पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाना, बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना, 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना और महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, जैसे 16 नए प्रावधान किए गये हैं।

बजट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आर्थिक विकास को तेज़ गति प्रदान करता है। जिसमें इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, पावर, ऑइल और गैस, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और नई टेक्नोलोजिकल और डिजिटल इकॉनमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । एम.एस.एम.ई. और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सरकार ने खुले दिल से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। सरकार ने 103 लाख के इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन के तहत, 6500 आधारभूत ढ़ांचे के प्रोजेक्ट चिन्हित किए है। इन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेशको के लिए ब्याज, डिविडेन्ट और कैपिटल गेन टैक्स में 100% की छूट दी है और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खर्चों का समावेश भी किया हैं। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक शुरु करने है और तीन साल का लॉक इन समय भी रखा गया है। सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स देने का भी निर्णय लिया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जन कल्याण, समाज के सभी वर्ग जैसे महिला, वृद्ध, युवा, मध्यम आय वर्ग और उपभोक्ताओं के लिए 'सबका साथ सबका विकास' की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार की सभी पूर्ववर्ती जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान पूरी तरह चालू रखे गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत किया जाएगा। एसपिरेशनल जिलों में जल आपूर्ति का घोषणा की गई है।

करदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल टेक्स पेयर राईटस चार्टर के द्वारा सरकार ने क़ानून के ही अन्तर्गत की है। इस तरह के प्रावधान अभी तक विश्व के केवल तीन देशों में ही हैं। विवाद से विश्वास, फेसलेस अपील और इ-असेसमेन्ट जैसे प्रावधान ईमानदार करदाताओ को सम्मान एवं कर सरलीकरण प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दरों में कम करने के साथ विकल्प देने का महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है और 15 लाख तक के मध्यम वर्ग के कर दाताओं को इस विकल्प से राहत मिलेगी। आम जनता, जो कि अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई को बैंक में डिपॉजिट के रुप में रखती है, को ध्यान में रखते हुए उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया है।

वित्त क्षेत्र के लोगों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है। बांड मार्किट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। विदेश से पूंजी आयात के लिए विदेशी निवेशकों को खासकर पेंशन एवं प्राविडेन्ट फंड के लिए घरेलू बांड मार्किट में निवेश की सीमा बढ़ाने और नई सरकारी योजनाओं में निवेश के प्रावधानों की घोषणा की गई है।

चीन और आस पास के देशों से भारत में सस्ता माल भेजा जा रहा है जिसके कारण हमारे देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। आसियान देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट के तहत जो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी और कन्ट्री ऑफ ओरिजिन जैसे प्रावधानों द्वारा इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में बैंकों के कर्ज के तहत समस्याए उपस्थित हो गई थीं, उसके समाधान को भी सरकार ने आसान किया है। लोन रि-स्ट्रक्चर करने की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ करना इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अनुपालन में सुविधा को ध्यान में रखा गया है। टैक्स ऑडिट करवाने की सीमा को एक करोड़ से बढाकर पांच करोड़ करने की आवश्यकता को भी पूरा किया गया है। देश के विकास एवं समाज के सभी वर्ग के कल्याण को सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की समस्या हो या युवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा में बदलाव हो। शिक्षा के लिए 99 हजार करोड़ रुपये के बजट का आवंटन, मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इस क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। निश्चित तौर पर यह बजट कई दूरगामी परिणाम लाएगा। ■

(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।)

क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए श्रीलंका सरकार का संकल्प स्वागत योग्य है: नरेन्द्र मोदी

श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंदा राजपक्षे 7 फरवरी को भारत पहुंचे। वे देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 8–11 फरवरी, 2020 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया। 8 फरवरी मुख्य कार्य दिवस रहा जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका अनादि काल से पड़ोसी भी हैं, और घनिष्ठ मित्र भी हैं। हमारे संबंधों के इतिहास का ताना-बाना संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, कला और भाषा जैसे अनगिनत रंग-बिरंगे धागों से बुना गया है। चाहे सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था या सामाजिक प्रगति, हर क्षेत्र में हमारा अतीत और हमारा भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में स्थायित्व, सुरक्षा, और समृद्धि भारत के हित में तो है ही, पूरे हिन्द महासागर क्षेत्र के हित में भी है और इसलिए, इंडो-पेसिफ़िक क्षेत्र में भी शांति और खुशहाली के लिए हमारा घनिष्ठ सहयोग बहुमूल्य है। हमारी सरकार की 'पड़ोसी प्रथम नीति' और 'सागर' डॉक्ट्रिन के अनुरूप हम श्रीलंका के साथ संबंधों को एक विशेष प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के श्रीलंका सरकार के संकल्प का हम स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या का डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में 'ईस्टर डे' पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ़ श्रीलंका पर ही नहीं, पूरी मानवता पर भी आघात थे और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। दोनों देशों की एजेंसीज के बीच संपर्क और सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि इस बातचीत में हमने श्रीलंका में संयुक्त आर्थिक परियोजनाएं पर और आर्थिक, व्यापारिक, और निवेश संबंधों को बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया। हमने अपने जन-जन से संपर्क बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने, और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की।

चेन्नई और जाफ़ना के बीच हाल ही में सीधी फ्लाइट की शुरुआत, इसी दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा है। इस सीधी फ्लाइट से श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र की तमिल जनसंख्या के लिए कनेक्टिविटी के विकल्प बढ़ेंगे और यह इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी

लाभकारी होगी। इस फ्लाइट को मिला अच्छा प्रतिसाद हम दोनों के लिए प्रसन्नता का विषय है। इस संपर्क को और बढ़ाने, सुधारने, और स्थाई बनाने के लिए और प्रयास करने पर भी हमने चर्चा की।

श्री मोदी ने कहा कि श्रीलंका के विकास प्रयासों में भारत एक विश्वस्त भागीदार रहा है। पिछले साल घोषित नई लाइन्स ऑफ क्रेडिट से हमारे विकास सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। हमें ख़ुशी है कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में आतंरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 48,000 से ज्यादा घरों के निर्माण का इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा अप-कंट्री क्षेत्र में भारतीय मूल के तमिल लोगों के लिए कई हज़ार घरों के निर्माण का कार्य भी प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री राजपक्ष और मैंने मछुआरों के मानवीय मुद्दे पर भी चर्चा की। इस विषय का प्रभाव दोनों देशों के लोगों के जीवनयापन पर सीधे रूप से पड़ता है और इसलिए हम इस मुद्दे पर रचनात्मक और मानवतापूर्ण एप्रोच जारी रखने पर सहमत हैं।

उन्होंने कहा कि श्रीलंका में री-कन्सीलिएशन से सम्बंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि श्रीलंका के संविधान में तेरहवें संशोधन को लागू करने के साथ-साथ री-कन्सीलिएशन की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। श्री मोदी ने कहा कि मैं एक बार फ़िर प्रधानमंत्री राजपक्ष का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से भारत और श्रीलंका की मैत्री और बहु-आयामी सहयोग और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही, दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के लिए सहयोग भी बढ़ेगा। ■

'गगनयान मिशन' भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धिः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नये वर्ष और नये दशक के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में 26 जनवरी को 'गगनयान' मिशन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत 2022 में अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा और देश को गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में किसी भारतीय को पहुंचाने के अपने संकल्प को पूरा करना होगा।

उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन 21वीं शताब्दी में भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। यह नये भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के उन चार पायलटों की सराहना की, जिनका चयन मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में किया गया है और उन्हें रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि ये होनहार युवा भारत के कौशल, प्रतिभा, क्षमता, साहस और सपनों का प्रतीक हैं। हमारे चारों मित्र कुछ ही दिनों में प्रशिक्षण के लिए रूस जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से भारत और रूस की मैत्री और सहयोग में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों के कंधों पर देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं तथा अंतरिक्ष में उड़ान भरने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं चारों युवाओं, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों और इस मिशन से जुड़े इंजीनियरों को बधाई देता हूं।

हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और शांति हर सवाल के जवाब का आधार होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि एकजुटता से हर समस्या के समाधान का प्रयास हो और भाईचारे के जरिये हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करें।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम इक्कीसवीं सदी में हैं, जो ज्ञान-विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो?'' उन्होंने पूछा, ''क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है, जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हों?"

श्री मोदी ने कहा कि हिंसा, किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल, कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक-से-अधिक उसका समाधान ढूंढ़कर ही हो सकता है।

जल शक्ति अभियान में तेजी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा कि जल शक्ति अभियान लोगों की भागीदारी से गति पकड़ रहा है। उन्होंने देश के प्रत्येक कोने में जल संरक्षण के लिए कुछ विस्तृत और नवोन्मेषी प्रयासों को साझा किया।

राजस्थान में जालौर जिले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां दो ऐतिहासिक कुओं को कूड़ा फेंकने और गंदे पानी का स्थान बना दिया गया था, लेकिन एक दिन भद्रायन और थानावाला पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत उसमें नई जान डालने का संकल्प लिया। वर्षा से पहले लोग उसकी सफाई में जुट गए और उस कुएं से कूड़ा और काई निकाली। इस अभियान में कुछ दान की गई राशि; अन्य प्रकार के श्रम का इस्तेमाल किया गया। इसके परिणामस्वरूप ये कुएं इस समय लोगों की जीवन रेखा हैं।

इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गांव वालों के सामूहिक प्रयास से सराही झील जीवंत हो गई। एक अन्य उदाहरण अलमोड़ा-हल्द्वानी राजमार्ग पर स्यूनराकोट गांव में जन भागीदारी का है। यहां गांव वालों ने खुद सुनिश्चित किया कि पानी उनके गांव तक पहुंचे। लोगों ने धनराशि जमा की और श्रम दान किया। गांव में एक पाइप बिछाई गई और पम्पिंग स्टेशन लगाया गया। इससे दशकों पुरानी जल संकट की समस्या का समाधान हो गया।

प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे #Jalshakti4India का इस्तेमाल करते हुए जल संरक्षण और जल सिंचाई के ऐसे प्रयासों की अपनी कहानियां साझा करें। जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल शक्ति अभियान की शुरुआत जुलाई 2019 में पिछले मानसून में की गई थी। इस अभियान में पानी की कमी वाले जिलों और ब्लॉकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। ■

राजपथ पर दिखी भारत की आन-बान-शान की तस्वीर

देश के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को विजय चौक से ऐतिहासिक लाल किले तक देश की आन-बान-शान का शानदार नजारा देखा गया जहां भारत की अनूठी एकता में पिरोई विविधताओं वाली विरासत, आधुनिक युग की उसकी उपलब्धियां और देश की सुरक्षा की गारंटी देने वाली फौज की क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

इस साल गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जेयर मेसियस बोलसोनारो थे। उन्होंने राजपथ पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भव्य परेड को देखा।

सलामी मंच पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में राजपथ पर भारत की संस्कृति के रंगों और रक्षा क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन किया गया। अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों एवं जहाजों और भारतीय सैनिकों के दस्तों ने किसी भी चुनौती से निपट सकने की देश की ताकत का अहसास कराया।

सबसे अंत में रोमांच से भर देने वाले युद्धक विमानों को राजपथ के उपर से हैरतअंगेज कारनामों के साथ उड़ान भरते देखा गया। इन विमानों की ताकत के साथ ही वायुसेना के पायलटों का हुनर और जांबाज़ी का अहसास हुआ।

परेड के 8 किलोमीटर के रास्ते में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और बुजर्गों के चेहरों की चमक और उत्साह देखते ही बनता था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर साफा बांधने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस पर केसरिया रंग का 'बंधेज' का साफा बांधा। पारंपरिक कुर्ता पाजामा और जैकेट पहने प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति के बजाय पहली बार यहां नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ■

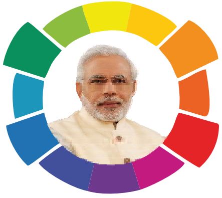

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

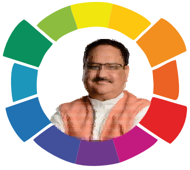

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1).............................. (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :.............................. दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राजपथ पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जेयर मेसियस बोलसोनारो

नई दिल्ली में बजट सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बलिदान दिवस (30 जनवरी) के अवसर पर नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कोकराझार (असम) में ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हुए भव्य समारोह में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल व अन्य

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंदा राजपक्षे

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20